समक्ष रणजीत सिंह माननीय न्यायमूर्ति

जोगिंदर सिंह -*याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य- *प्रतिवादी*

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7907

21 जुलाई 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226—हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1987—नियम 7—प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन—जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को बरी करना—याचिकाकर्ता को राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए दंड देने वाले प्राधिकारी का जांच अधिकारी से मतभेद होना—कारण बताओ नोटिस—याचिकाकर्ता जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रहा है—प्रस्तावित प्रतिवाद का कोई पूर्ण और निष्पक्ष अवसर नहीं याचिकाकर्ता को दी गई कार्रवाई - ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर आवश्यक है ताकि कोई व्यक्ति जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से असहमत होने पर अपनाए गए दृष्टिकोण का विरोध कर सके - याचिका की अनुमति दी गई, पेंशन में कटौती करने का आदेश दिया गया और स्वतंत्रता प्रदान करते हुए 10% हानि की वसूली को अलग रखा गया उत्तरदाताओं को मामले पर पुनर्विचार करने और कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए कहा गया है।

अभिनिर्धारित कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध करने का पूर्ण और निष्पक्ष अवसर नहीं दिया गया। यह एक ऐसा मामला है जहां जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था। दंड प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होते हुए एक असहमति नोट दर्ज किया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर आवश्यक था ताकि व्यक्ति जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से असहमत होते हुए अपनाए गए दृष्टिकोण का विरोध कर सके। याचिकाकर्ता को न केवल दंडित किया गया है, बल्कि उस पर पर्याप्त दायित्व का बोझ भी डाला गया है। आने वाले समय में उनकी पेंशन कम रहेगी। यह बिल्कुल उचित है कि याचिकाकर्ता को सुना जाए और उसके बाद उचित आदेश पारित किया जाए। देरी के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति पर विचार न करने का कठोर और तकनीकी दृष्टिकोण कठोर प्रतीत होगा। विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

(Para 5)

कमल सहगल की ओर से अमित राव, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।*

राज्य के लिए हरीश राठी, वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा।

रणजीत सिंह, न्यायमूर्ति (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में शामिल हुए। 27.5.1964. वर्ष 1997 से 1999 के बीच याचिकाकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे। वह 30.9.1999 को सेवानिवृत्त हुए।उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बहुत बाद, 8.3.2002 को, याचिकाकर्ता को आरोपों का एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल ने उनके खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील), नियम 1987 के नियम 7 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया है।

2. याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल, फरीदाबाद द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के लिए निविदा को मंजूरी देते समय, उन्होंने सामग्री पर ध्यान नहीं दिया और परिणामस्वरूप गावर सहकारी एल/ के पक्ष में निविदा की अनुमति दे दी। सी सोसायटी, हिसार, किलोमीटर को छोड़े बिना , जहां पूर्व-मिश्रित कालीन का काम अप्रैल 1998 से सितंबर 1998 के दौरान पहले ही किया जा चुका था। जांच अधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए विस्तृत किया गया था। याचिकाकर्ता ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने अपने बचाव के समर्थन में दस्तावेज़ पेश किये थे। इसके बाद जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया गया।

3. हालाँकि, दंड प्राधिकारी ने उन्हें असहमति नोट और जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनका अस्थायी तौर पर मानना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुआ और याचिकाकर्ता 32,85,030/- रुपये की हानि का दोषी था। तदनुसार, 3,28,503/- रुपये जो हानि का 10% है राशि की वसूली के साथ उनकी पेंशन में 20% की कटौती करने का प्रस्ताव किया गया था ।याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।

4. 14.3.2008 का कारण बताओ नोटिस 5.4.2008 को प्राप्त हुआ। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने दिनांक 8.4.2008 को अपने संचार के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने की मांग की क्योंकि उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था। दंड प्राधिकारी ने इसके बजाय याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 20.5.2008 तक का समय दिया था। 15.5.2008 को याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए प्रार्थना की। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार करने के बजाय उसे 10.6.2008 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया। 9.6.2008 को, याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए 7 से 10 दिनों के समय के लिए फिर से प्रार्थना की। इसके बजाय उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को अंतिम अवसर के रूप में 20.7.2008 तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता को 24.7.2008 को दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रदान की गईं,

जो याचिकाकर्ता के अनुसार, हालांकि 7.8.2008 को वितरित की गईं। याचिकाकर्ता जवाब दाखिल करने के लिए 5.8.2008 को कार्यालय गया, जब उसे बताया गया कि मामले का निपटारा पहले ही हो चुका है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने देरी को माफ करने और उसके जवाब पर विचार करने का अनुरोध किया, जिस पर भी सहमति नहीं हुई और विवादित आदेश बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ता ने तदनुसार सजा के साथ-साथ इस आधार पर कार्रवाई के लिए यह रिट याचिका दायर की है कि उसे खुद का बचाव करने के लिए उचित अवसर से वंचित किया गया था, खासकर तब जब जांच अधिकारी ने उसे बरी कर दिया था।

5. रिट याचिका में किए गए दावों की वैधता या उसकी प्रामाणिकता पर जाए बिना, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध करने का पूर्ण और निष्पक्ष अवसर नहीं दिया गया था। यह एक ऐसा मामला है जहां जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था। दंड प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होते हुए एक असहमति नोट दर्ज किया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर आवश्यक था ताकि व्यक्ति जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से असहमत होते हुए अपनाए गए दृष्टिकोण का विरोध कर सके। याचिकाकर्ता को न केवल दंडित किया गया है बल्कि उस पर पर्याप्त दायित्व का बोझ भी डाला गया है। आने वाले समय में उनकी पेंशन कम रहेगी। यह बिल्कुल उचित है कि याचिकाकर्ता को सुना जाए और उसके बाद उचित आदेश पारित किया जाए। देरी के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति पर विचार न करने का कठोर और तकनीकी दृष्टिकोण कठोर प्रतीत होगा। विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। हालाँकि, उत्तरदाता इस मामले पर पुनर्विचार करने और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। याचिकाकर्ता, यदि चाहे तो, अतिरिक्त दलीलें दायर करके उत्तर में की गई अपनी दलीलों को पूरक कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसे तीन सप्ताह की अवधि दी जाती है। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता का अनुरोध, यदि किया जाता है, तो उस पर भी कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है और अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा